

प्रशासकीय काल में पूर्व एडीओ आईएसबी व सचिव ने लाखों डकारे

कैनविज टाइम्स संवाददाता



सकरन सीतापुर। सकरन विकास खंड क्षेत्र में प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी लेने वाले पूर्व सचिव व एडीओ आईएसबी पर बगैर काम कराए। साथे 16 लाख की धनराशि हड़पने का आरोप है उक्ते ऊपर लगे आरोगी की जांच डीपीआरओ ने की है। सूत्र बताता है कि मूल्यांकन में आरोगी की पुष्टि होती मिलती है।

ऐसे चर्चा सकरन विकासखंड क्षेत्र में है सकरन विकासखंड की ग्राम पंचायत सकरन में वर्ष 2021 में मार्च महीने में हुए पंचायत चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागी थी आचार संहिता नवंबर 2020 में चुनाव आयोग द्वारा लगा दी गई थी तब ग्राम पंचायत के प्रशासक तकालीन एडीओ आईएसबी जिम्मेदार कुमार रस्तोगी जो वर्तमान में ब्लाक रामपुर मध्यप्रदेश में तैनात है तथा पंचायत सचिव अपेत

चल रहे मानक विहीन नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड केंद्र

कैनविज टाइम्स संवाददाता



तथाकथित केंद्रों पर या तो टेक्नीशियन के सहारे कार्य किया जा रहा है या फिर ज्ञालालाप लोग मरीजों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। पीन डीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए कड़ि नियम बनाए गए हैं। लेकिन, परस्पर, कर्नलमंज, कटांबउर में खुले सेंटरों पर नियमों खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। लाभ कमाने हैं मूल उद्देश्य अधिकारी लाभ कमाना है। इसके लिए मरीजों व तीमारदारों का दौनन करते हैं। स्ट्रों की मानें तो इसके लिए नियमी अस्पताल संचालकों द्वारा एक एक्ट त्रिभिन्न नर्सिंग होम में आधा दर्जन से अधिक नर्सिंग होम अस्पताल त्रिभिन्न नर्सिंग होम मरीजों की अन्वेषणीय कर चला जाए जा रहे हैं। विधायीय जिम्मेदारों की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की मरीजों का आधिकारिक शोषण कर रहे हैं। स्ट्रों की मानें तो कई अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों से जमकर धन आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अजान बने हुए हैं। अल्ट्रासाउंड केंद्रों में भी फर्जीवाड़ा यही हाल अल्ट्रासाउंड केंद्रों का भी है। इन

योगी जी : यहां गरीब को न्याय नहीं मिलता, गोप्ता पुलिस से उठ चुका है भरोसा

फिटर गजेंद्र सिंह की मौत के बाद उसी पर दर्ज हुआ मुकदमा...

दो माह से चल रहा था विवाद, तीन बार मोतीगंज थाने पर पहुंचा मामला...

समय पर मोतीगंज पुलिस कर देती करवाई तो बच जाती गजेंद्र सिंह की जान....

मोतीगंज पुलिस की लापरवाही बनी चीनी मिल के फिटर गजेंद्र सिंह की मौत की वजह...



मृतक गजेंद्र सिंह

फोटो मृतक की पत्नी और उसके बच्चे। तैनात गजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी कर रही थी। बैकमूर गजेंद्र सिंह चीनी मिल के अधिकारियों की प्रताङ्का तीन महीने से सहता आ रहा था। गजेंद्र सिंह मिल के अधिकारियों के खिलाफ मोतीगंज थाने में लगातार शिकायत कर रहा था लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया।

बजाज चीनी मिल कुंदरखी में फिटर मैकेनिक के पद पर कार्यरत गजेंद्र सिंह का मिल के यूनिट हेड व एचआर मैनेजर समेत तीन अधिकारियों से पिछले दो माह से विवाद चल रहा था। इस दौरान तीन बार मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन मिल के अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई कर रहा था लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया।

का स्थाई समाधान कराया गया। इतना ही नहीं, प्रताङ्का को आमदाह का प्रयास किया तब भी मोतीगंज पुलिस ने चीनी मिल के अधिकारियों पर एकशन लेने के बजाय पीड़ित गजेंद्र के ही खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की दी थी।

बताते हैं कि बजाज हिन्दुस्थान चीनी मिल कुंदरखी किंवदं में फिटर मैकेनिक के पद पर कार्यरत गजेंद्र सिंह ने मिल के यूनिट हेड पीएन सिंह एचआर मैनेजर कमलशे कुमार व राजू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2024 अक्टूबर माह की 22 तारीख को वह अपने घर से लापता हो गया था। इसकी सूचना मोतीगंज पुलिस को

दी गई। पुलिस व एसओजी टीम ने गजेंद्र को लखनऊ से बरामद कर गोप्ता लाई और चीनी मिल के अधिकारियों व गजेंद्र के बीच सुलह-समझौता करा दिया था। हालांकि, इसके बाद भी गजेंद्र की दुश्मानियों कम नहीं हुई। चीनी मिल के अधिकारियों की प्रताङ्का से तंग आकर उसने 28 नवंबर को आमदाह का प्रयास किया तब भी मोतीगंज पुलिस ने चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा उसे बचा रखा गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इकाहोबा चीनी प्रधानी पर एकशन लेने के बजाय पीड़ित गजेंद्र के ही खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की दी थी।

बताते हैं कि बजाज हिन्दुस्थान चीनी मिल कुंदरखी किंवदं में फिटर मैकेनिक के पद पर कार्यरत गजेंद्र सिंह ने मिल के यूनिट हेड पीएन सिंह एचआर मैनेजर कमलशे कुमार व राजू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2024 अक्टूबर माह की 22 तारीख को वह अपने घर से लापता हो गया था। इसकी सूचना मोतीगंज पुलिस को

दी गई। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोतीगंज पुलिस ने फिटर मैकेनिक गजेंद्र सिंह की मौत के तुरंत बाद ही बजाज चीनी मिल कुंदरखी के एचआर कमलशे कुमार की तहरीर पर सुक्रवार की रात 11.34 बजे मृतक गजेंद्र के खिलाफ ही एसओजी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में युक्तमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि, इसके बाद भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। विधायीय मिलीभगत से इन अवैध केंद्रों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। इन अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों व तीमारदारों का शोषण किया जाता है। तैसीसील नर्सिंग होम बनाए गए हैं। लेकिन, परस्पर, कर्नलमंज, कटांबउर में खुले सेंटरों पर नियमों खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। लाभ कमाने हैं मूल उद्देश्य अधिकारी लाभ कमाना है। इसके लिए मरीजों व तीमारदारों का दौनन करते हैं। स्ट्रों की मानें तो कई अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाकर इलाज के नाम पर मरीजों खुले सेंटरों में भी फर्जीवाड़ा की खाता कमाल नीति के चलते अस्पताल संचालक ग्रामीण क्षेत्र की जांच आगाही की जा रही है। सबकुछ जानते हुए आधिकारी लाभ कमाने हैं। इसके लिए अस्पताल बैगर पंजीकरण के ही बोरोक टोक चल रहे हैं। यहाँ नहीं अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही मूलभूत संसाधन नर्सिंग होम में फर

खेलने की उम्र में ब्याह

इकीसर्वों सदी के भारत में यदि हर पांच में से एक लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाए तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। पिछले एक वर्ष में दो लाख बाल विवाह कानून की सख्ती से रोक गए। निश्चित रूप से बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। जिससे बच्चियां ताउप्र पढ़ाई से बंचित हो जाती हैं और उनका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सही मायानों में बाल विवाह कुपोषण एवं गरीबी का ऐसा चक्र पैदा करता है जिसकी कीमत राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। चाँकाने वाले आंकड़े हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार व त्रिपुरा में 40 फीसदी लड़कियों के विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं। यही वजह है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। दरअसल, यह शुरुआत उन राज्यों को लेकर की गई है, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तथ्य यह भी कि समाज में गरीबी और बाल विवाह में सीधा रिश्ता है। एक अध्ययन के अनुसार 75 फीसदी बाल विवाह गरीब परिवारों में होते हैं। जो कालांतर गरीबी के नये दुश्चक्र को जन्म देते हैं। निश्चित रूप से हमारे समाज में गरीबी व रुद्धिवाद के चलते इस कुप्रथा को बल मिलता है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि संपन्न, शिक्षित और प्रगतिशील समाजों में बाल विवाह के मामले सामान्यतर नजर नहीं आते। वहीं दूसरी ओर लिंगभेद की सोच भी इन विवाहों को बढ़ावा देती है। अभिभावक विषम परिस्थितियों के चलते अल्पवयस्क लड़कियों का विवाह करके जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। यह सबाल उठना स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता से पूर्व देश में वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून बनने के बावजूद इस कुप्रथा पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया। पहले धारणा थी कि असुरक्षाबोध के चलते बाल विवाह को बढ़ावा मिलता रहा है। कम से कम स्वतंत्र भारत में बाल विवाह की सोच नहीं रहनी चाहिए थी। निस्संदेह, राजग सरकार के दैशन बाल विवाह उन्मूलन के लिये सार्थक प्रयास किए गए। हालिया बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत से पहले भी सरकार ने इस दिशा में पहल की थी। इससे पहले वर्ष 2006 में बाल विवाह कानून में सुधार किया गया। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 21 व लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। वहीं वर्ष 2021 में राजग सरकार ने 2006 के कानून में सुधार करके लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव किया था। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भारत में 40 फीसदी के करीब लड़कियों के 18 साल से कम उम्र में विवाह होने की बात कहती है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल फैमिली हेल्प सर्वे हर रोज चार हजार से अधिक बाल विवाह होने का उल्लेख करते हैं। बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में असम सरकार की सफलता का अकसर जिक्र होता है, जहां आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक बाल विवाह की दर को पांच फीसदी से नीचे लाया जाए। निस्संदेह, बाल विवाह जहां बच्चियों के मौलिक अधिकारों का हनन है, वहीं उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को भी कमतर करता है। इससे जहां लड़कियों के अधिकारों का अतिक्रमण होता है, वहीं उनके शोषण का भी खतरा रहता है। पढ़ाई बीच में छूट जाने से उनके सपने मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कम उम्र में शादी और बच्चे होने से उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सम्पन्न करना पड़ता है। पूरी पढ़ाई न होने तथा नौकरी न कर पाने की स्थिति में वे अर्थिक रूप से परियों पर आन्तरिक हो जाती हैं। जिससे उनका स्वाभाविक विभेद का सामना भी करना पड़ता है। बाल विवाह का होना यह भी बताता है कि हमारे समाज में अभी दहेज प्रथा का दबाव कम नहीं हुआ है। जिससे बचने के लिये अभिभावक तुरत-फुरत अल्पवयस्क लड़कियों की शादी कर देते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी कि सिर्फ कानून बनाने से ही इस कुरीति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, समाज में जागरूकता लाने के लिये भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना होगा।

प्रदूषण से बढ़ती मौतों के लिये कौन जिम्मेदार?

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर विशेष

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद, प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों, नीतियों, और प्रदूषण को कम करने के महत्व पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन भौपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। यह त्रासदी 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को हुई थी। इस त्रासदी में ज़हरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। देश एवं दुनिया की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिन्हां का बड़ा कारण है। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली सवित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। प्रदूषण के लाख लाग पापु प्रदूषण से भर हा गहा रफ पूरा दुनिया न इस पव भरन पाला का पुल सख्ता का प्ररन ह ता वह करवा 81 लाख बतायी जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही एवं लापरवाही को ही दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से यह प्रदूषण फैल रहा है और किस तरह वे इससे बचाव कर सकते हैं। प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसकी जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेपरवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? देश की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रुबरु है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है।

अलग वजहों से
‘तेज़ रास्ता’



धूएं का नियमन न होने जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्पत्ति ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है। यूनीसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से 1 लाख 69 हजार बच्चे जिनकी औसत आयु पांच साल से कम बतायी गई है, मौत के शिकार होते हैं। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इनका समुचित शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फ्रेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित होना हैं। हमारे लिये चिंता की बात यह है कि बहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है। हर कुछ समय बाद अलग-करने में जरा नहीं हिचकिचा रहे जो हवा को जहरीला बना रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है। उसके बाद उच्च रक्तचाप, कुपोषण तथा तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों का नंबर आता है। दरअसल, गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बड़ी आवादी येन-केन-प्रकारेण जीविका उपार्जन में लगी रहती है, उसकी प्राथमिकता प्रदूषण से बचाव के बजाय रोटी ही है। वहीं ढुलमुल कानूनों, तंत्र की काहिली तथा जागरूकता के अभाव में वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर पहल नहीं हो पाती। मुश्किल यह है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की बजाए से जमीन से उठने वाली धूल, पराली की धूंध और वाहनों से निकलने वाले धूएं के छंटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजन, वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सरकारें नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालिएपन के कागर पर खड़ी है। देश में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के आंकड़े इस वास्तविकता को उजागर करते हुए प्रदूषण की समस्या का कोई दीर्घकालिक और ठोस हल निकालने के लिये चेता रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, विचार और योजनाएं बनानी चाहिए। -ललित गर्ग

भी होते

अगर आप सोचते हैं कि वायु प्रदूषण से केवल फ़ेफड़े या श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं, तो दुबारा विचार करें। क्योंकि मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण से अधिक से अधिक लोग अपनी विधिवत वायु साक्षरता से बाहर आईं हैं। इसका अर्थ यह है कि वायु प्रदूषण ने आपकी विधिवत वायु साक्षरता को बढ़ावा दिया है।

जराय जानु युवतीया स आज्ञा कर रास्तरेनै
भी हो सकती है, यह सिमें कोरिन्या को होनेवाली
क्षति भी शमिल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूय
ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) के
ऑप्थामोलोजिस्ट डॉ. राजेश सिन्हा ने
आईएएनएस को बताया कि नाक और मुँह की
तरह आंखों को ढकना काफी मुश्किल है। इससे
फेफड़ों की तरह ही आंखों पर भी वायू प्रदूषण
का बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि आंख
की ओकुलर सतह वातावरण के सीधे संपर्क
आती है, इसलिए यह वायू प्रदूषण से सबसे
ज्यादा प्रभावित होती है। सर गंगा राम हॉस्पिटल,
दिल्ली के ऑप्थामोलोजिस्ट डॉ. टिकू बाली
राजदान ने बताया कि कई सालों तक प्रदूषण के
संपर्क में रहने के कारण कोरोना को क्षति
पहुंचती है, यह तुरंत नहीं होता है। अगर ड्राई

प्रदूषण के संपर्क से ड्राई आई की समस्या या
आंखों के पानी की युग्मवत्ता खराब हो जाती है।
इससे आंखों में खुजली, परेशानी और लाल होने
की समस्याएं होने लगती हैं।'' सिन्हा का कहना
है, ''जो लोग कॉटैक्ट लेंस पहनते हैं, उन्हें
जोखिम और बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी आंखें
पहले से ही ड्राई होती हैं। ऑप्थामोलोजिस्ट्स
का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने से ओपीडी में
एलजी के इलाज के लिए आनेवाले मरीजों की
संख्या बढ़ी है। मैक्स हेल्थकेयर के आंख
विभाग के निदेशक और प्रमुख डॉ. संजय धनव
का कहना है कि आंखों में खुजली, परेशानी और
नजर कमजोर होने की समस्या से पीड़ित मरीजों
की संख्या बढ़ी है तथा इम्युनिटी कम होने के
कारण ड्राई आई और अन्य संक्रमण बढ़े हैं।

गवान श्रीवा

पौराणिक मंत्र सभी मंत्र को जपने से पूर्व एक बार ? श्री कृष्णाय शरणं मम । मंत्र का उच्चारण अवश्य करें । पहले मंत्र के लिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखें । सान पश्चात् कुश के आसन पर बैठकर सुबह और शाम संध्या तृणं के समय उक्त मंत्र का 108 बार जपा करें । यह मंत्र जीतन में

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय

नमो नमः ॥ दूसरा मंत्र संकटकाल में दोहराया जाता है। जब कभी भी व्यक्ति को आकर्षिक संकट का सामना करना पड़ता है तो तुंतं ही पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उक्त मंत्र का जाप कर संकट से मुक्ति पाई जा सकती है।
 ॐ नमः भगवते गासुदेवाय कृष्णाय, कलेशनाशाय गोविदाय नमो नमः । तीसरा मंत्र निरंतर दोहराते रहना चाहिए। उक्त मंत्र को चलते-फिरते उठते-फैलते ३४ कठीनी भी किसी भी क्षा में दोहराने जर्ने से कषा ये ज्ञात उठता

बेटत आर कहा भा किसा भा क्षण म दाहरात रहन स कृष्ण स जुङाप रहे है। इस तरह से श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने से व्यक्ति कृष्ण धारा जुड़कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पृष्ठ कर लेता है।

‘हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम-र हरे-हरे। कृष्ण मंत्रों का महत्व-उक्त मंत्र के महत्व को समझते हुए अन्य और जो अपना मन नहीं लगाता वह कृष्ण की शरण में होता है और जो कृष्ण की भाषाएं हैं उसे किसी भी पाकाम के रोपा और प्रोक्त गति नहीं मारते।



स्थित बरोग बहुत ही खूबसूरत जगह है। जहां जाकर आप 2 से 3 दिनों की छुटियां सुकून से बिता सकते हैं। चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ बड़ोग, बेशक शिमला, मनाली जैसी बहुत मशहर जगह गया है। बड़ोग रेलवे स्टेशन के निर्माण को गति देने के लिए पर्वत के दोनों ओर खुदाई करने का आदेश दिया गया था। हालांकि बाद में यह पता चला कि इंजीनियर बड़ोग का अनुमान गलत होने के कारण टनल के दोनों सिरे आपस में

नहीं लेकिन वीकैड में छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बरोग का रेलवे स्टेशन यहां देखने वाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। जहां तक पहुंचने का रास्ता भी पहाड़ियों से होकर आता है। यहां आप टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं। ज्यादातर ट्रिस्ट शिमला की यात्रा करते समय चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पर कालका-शिमला हाइवे पर स्थित बड़ोग में रुकना पसंद करते हैं। बड़ोग में कालका-शिमला रेल मार्ग पर सुरंग नंबर 33 है। इसकी लंबाई 1143.11 मीटर है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर एच. एस. हैरिंटन द्वारा जुलाई 1900 से सिंतबर 1903 के बीच किया गया। दरअसल, इस शहर का नाम इसी पर्याप्ति के निर्णायक रूप से पड़ता है। शहर का में नहीं मिल सके। इस पर ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया। इस शर्मिंदी के कारण उहाँने आमहत्या कर ली। इंजीनियर बड़ोग का शब्द इस टनल के पास ही दफनाया गया और बाद में उनके नाम पर इस गांव का नाम बड़ोग रखा गया। यह विश्व की सबसे सीधी टनल के रूप में जानी जाती है। यहां का रेलवे स्टेशन स्कॉटिश स्टाइल में बना है, जो बहुत आकर्षक है। रेणुका लेक-बड़ोग की ये जगह है फ्रेमस ट्रिस्ट स्पॉट। जो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेचुरल लेक में से एक है। समुद्र तल से करीब 672 मीटर की ऊंचाई वाली इस झील का नाम भगवान परशुराम की मां रेणुका के नाम पर रखा गया है। घने जंगलों से घिरी इस झील के किनारे दो पांचियां भी हैं।

एड्स को लेकर समाज में खुले मन से चर्चा करने की जरूरत : नड़दा

एजेंसी

इंदौर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगतप्रकाश नड़दा ने आज कहा कि एड्स को लेकर पढ़ले की तुलना में काफी जागरूकता आयी है, लेकिन व्यापक जन जागरण के लिए समाज में खुले रूप से चर्चा करना आवश्यक है।

श्री नड़दा ने विश्व एड्स दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं संसद विष्णुदत्त शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। श्री नड़दा ने कहा कि एड्स किसी व्यक्ति को कई तरह से अपनी जाकड़ में ले सकता है। इसलिए इस पर मानना में खुले कर्चर आवश्यक है। तीन चार दशक की तुलना में एड्स को लेकर जागरूकता आयी



है, लेकिन इसको लेकर व्यापक जन जागरूकता की जरूरत है। उस समय एड्स को लेकर मृत्यु का भय रहता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह से अन्य लोगों को भी समाजजनों के बाद से स्कूली विद्यार्थियों से भी चर्चा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है,

जिसके सेवन से एड्स दूर किया जा सके। इससे पर्दित मरीज को आजीवन दवा लेना पड़ता है और इसके सहाये वह बेहतर जीवन जी सकता है। इसलिए इस लाइलाज रोग पर नियंत्रण के लिए समाज जागरूकता के लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य ऐसे लोगों को मिलकर कार्य करना होगा।

